

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

वित्त अधिकारी,
इला चैक,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुमान

देहरादून दिनांक १५ फ़िल्ड 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए मुगतान योजनान्तर्गत द्वितीय एवं अन्तिम किस्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, हिल्ट्रान के पत्र संख्या: यूपीएचएलसी/सी एण्ड हल्व्य/टीपीटी/07-08/दिनांक 20 सितम्बर 2007 के संदर्भ में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड को घालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण विशेष सेवाओं के लिए मुगतान योजनान्तर्गत परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण हेतु शासनादेश संख्या 21/XXXIV/06-सूप्रौ०/2005 दिनांक 03 मार्च 2006 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रु० 234.95 लाख के अतिरिक्त योजना की लागत रु० 491.50 लाख के विपरीत अवशेष द्वितीय किस्त के रूप में रु० 15.00 लाख संगत मद से एवं रु० 241.55 लाख संलग्न वी० एम०-१५ में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में पुर्णविनियोग के द्वारा अर्थात् कुल रु० 256.55 लाख (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर हिल्ट्रान को उपलब्ध कराई जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि हिल्ट्रान के पी०एल०० में रखी जायेगी तथा इससे अर्जित समर्त व्याज की धनराशि को वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार राजकोष में जमा किया जायेगा। बैंक में धनराशि के आहरण की सूचना समय-समय पर शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3— वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत एवं भौतिक प्रगति के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उस स्थिति में अवशेष धनराशि का समर्पण शासन को किया जायेगा।

4— स्वीकृति के शेष सभी शर्ते उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 03 मार्च 2006 के अनुसार रहेगी।

5— जिस विभाग की योजना हो उनका अनुरोध, राज्य स्तर पर गठित समिति के परीक्षण हेतु प्रशासनिक विभाग सम्पूर्ण योजना, उसके लागत लाभ तथा आवश्यक टेक्नालॉजी के प्रयोग के साथ यह प्रमाण पत्र देंगे कि इसके लिए भारत सरकार या अन्य फन्डिंग का विकल्प नहीं है।

6— स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदबार व्यय विवरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर लिया जायेगा और इसका उपयोग दिनांक 31.3.2008 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा। उक्त योजना में व्यय की गई धनराशि का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

7— इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-23 के लेखांशीर्षक-4859-दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 02-इलैक्ट्रॉनिक्स-आयोजनागत, 800-अन्य व्यय, 03-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण-00-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 505/XXVII(2)/2007 दिनांक 20 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
श्री
(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: ८० (१) / ०६ / XXXIV / सूची ० / २००५, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर सचिव वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, हिल्ट्रान, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुशासन-2
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
व
(विजय कुमार ढौड़ियाल)
अपर सचिव

